दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 20 मार्च 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 170

महत्वपूर्ण एवं खास

शिवसेना सांसद ने की सिंगापुर में फंसे महाराष्ट्र के छात्रों को लाने गुहार

» राष्ट्रपति कोविन्द को लिखा पत्र

नईदिल्ली (आरएनएस)। शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर सिंगापुर में फंसे महाराष्ट्र के 50 छात्रों को तुरंत भारत वापस लाने की मांग की है। अपने पत्र में विनायक राउत ने कहा है कि 17 मार्च 2020 से ये छात्र सिंगापुर के एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इन छात्रों ने 18 मार्च को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से संपर्क साधा था। विदेश मंत्री ने इन छात्रों को तुरंत ही भारत लाने का आश्वासन दिया था, लेकिन कल देर रात तक इन छात्रों को वापस लाने का कोई इंतजाम नहीं किया किया गया है। विनायक राउत ने पत्र में यह भी कहा है, अभी तक भारतीय दूतावास ने इन छात्रों से संपर्क नहीं साधा है। गौरतलब है कि सिंगापुर एयरपोर्ट में फंसे ये स्टूडेंट फिलीपींस की राजधानी मनीला के एक मेडिकल कॉलेज पढ़ाई करते थे। सरकार ने पहले से ही फिलीपींस से आने-जाने वाली हवाई सेवा बंद कर रखी है, जिससे ये छात्र सिंगापुर आ गए थे और वहां फंस गए हैं।

सहकारी संस्थाओं में राजनीतिक नियुक्तियों पर लगे रोकः सोनी

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश में सहकारी समितियों और सहकारी बैंक की दशा सुधारने और इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की देख-रेख में लाने की गुरुवार को राज्य सभा में मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कैलाश सोनी ने विशेष उल्लेख के जरिए इस मसले को उठाते हुए कहा कि वैद्यनाथन आयोग ने सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों में राजनीतिक नियुक्तियां न करने की सिफारिश की थी। कई राज्यों में इस तरह के प्रावधान किये गये और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की राष्ट्रीय ग्रामीण एवं विकास बैंक ने आर्थिक मदद भी की है लेकिन अब नियमों को बदलकर कुछ राज्यों खासकर मध्य प्रदेश में अनेक सहकारी संस्थाओं के प्रशासक राजनेता नियुक्त कर दिये गये हैं। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को किसानों का कर्ज माफ करने के लिए बाध्य किया जा रहा है और राज्य सरकार इस मद की राशि भी उन्हें उपलब्ध नहीं करा रही है। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की हालत खस्ता हो जायेगी और किसानों की अंश पूजी पर खतरा मंडराने लगेगा। उन्होंने सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों में राजनीतिक नियुक्तियां न करने और इन्हें रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी में लाने का प्रावधान करने की सरकार से मांग की।

देश के 5 लाख रेस्टोरेंट 31 मार्च तक रहेंगे बंद

» कोरोना के चलते एनआरएआई का निर्णय

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस का खौफ दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. ऐसे में रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने भी कोरोना के प्रकोप को देखते हुए बंद करने का फैसला किया है. देश में 5 लाख रेस्टोरेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन (एनआरएआई) ने 18 मार्च से 31 मार्च तक रेस्टोरेंट बंद करने की एडवाइजरी जारी की है. इससे देश में तकरीबन 5 लाख रेस्टोरेंट बंद रह सकते हैं. हालांकि यह रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर निर्भर करता है कि वो बंद करने का फैसला लेंगे या नहीं. इससे सबसे ज्यादा वो लोग प्रभावित होंगे जो बाहर भोजन करते हैं। एनआरएआई अपने जारी किए गए बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमें ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है. इससे हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा. लेकिन ग्राहकों, कर्मचारियों और सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है. एनआरएआई कहा कि हमारे ज्यादातर कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. इस दौरान इन कर्मचारियों को कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा है।

राज्यसभा में हंगामे के बीच रंजन गोगोई ने ली शपथ

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने गुरुवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दौरान विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया और शेम..शेम के नारे लगाए। गोगोई की शपथ के विरोध में कांग्रेस व वामदलों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

राज्यसभा की गुरुवार को शुरू हुई बैठक के दौरान पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई शपथ लेने के लिए जैसे ही निर्धारित स्थान आसन पर पहुंचे, तो विपक्षी सदस्यों ने शेम-शेम के नारे लगाने शुरू कर दिए। देश के 46वें सीजेआई रहे गोगोई के शपथग्रहण के दौरान ही नारेबाजी करते हुए कांग्रेस और वामदलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सांसदों के इस बर्ताव को सभापति एम. सभपति वेंकैया नायडू ने असंतोषजनक बताते हुए सदस्यों को नसीहत दी। गौरतलब है कि तीन अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले गोगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए नामित किया था। विपक्ष के हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में कहा कि राज्यसभा की परंपरा रही है कि यहां प्रतिष्ठित लोग सदस्य बने हैं। उन्होंने कहा कि सीजेआई रहे गोगोई भी निष्पक्ष रूप से राज्यसभा में अपनी बात रखेंगे।

» विपक्ष ने मनोनयन के खिलाफ की नारेबाजी, सदन से वाकआउट

न्यायपालिका पर आघातः कांग्रेस

कांग्रेस ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित करने पर इसे संविधान और लोकतंत्र पर हमला करार देकर विरोध करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने कहा था कि केन्द्र की बीजेपी सरकार लगातार नीति और सिद्धांतों को तार-तार करने में लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाना न्यायपालिका पर आघात है।

पहले भी राज्यसभा पहुंचे चीफ जस्टिस

इस पूरे विवाद के बीच आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि देश में पहले भी चीफ जस्टिस के पद से रिटायर जजों को राज्यसभा भेजा जाता रहा है। इससे पहले मुहम्मद हिदायतुल्लाह और रंगनाथ मिश्रा भी चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होने के बाद राज्यसभा के लिए मनोनीत हो चुके हैं।

पूर्व चीफजस्टिस रंजन गोगोई ने साधी चुप्पी

कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इसको लेकर गोगोई पर सवाल उठाए। तब पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा था कि वह इस बारे में शपथ लेने के बाद बात करेंगे। आज गोगोई ने राज्यसभा में संसद सदस्य के तौर पर शपथ ले ली, लेकिन विपक्ष के सवालों को लेकर कोई बयान नहीं दिया। राज्यसभा में सदस्यता की शपथ लेने के बाद जब गोगोई संसद से बाहर निकल रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे विपक्ष के आरोपों पर जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। गोगोई ने सिर्फ इतना ही कहा कि वह इसपर कोई बयान नहीं देना चाहते हैं।

दो वाहनों में टक्कर के बाद लगी आग से 4 जिंदा जले

शाजापुर (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में बुधवार देर रात दो वाहनों की टक्कर में चार लोग जिंदा जलकर मर गए, जबकि अन्य दो झुलस गए। पुलिस ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी और कहा कि घायलों की हालत गंभीर है।

पुलिस ने कहा, लालघाटी थाना क्षेत्र के बायपास पतोली रोड पर एक वाहन पलट गया और पीछे से आ रहे वाहन ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों वाहनों में आग लग गई। वाहन सवारों को बड़ी मुश्किल गाड़ी से बाहर निकाला गया। बुरी तरह से झुलसने के बाद चार लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि अन्य दो की हालत गंभीर बनी हुई है। एक वाहन में अंगूर की पेटियां भरी थी और अन्य वाहन में मुर्गियां थीं। पुलिस के अनुसार, वाहनों में टक्कर के बाद लगी आग से बडी संख्या में मुर्गियों की मौत हुई है। इस हादसे के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अमला पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश की।

बैंकों को संकट से बचाने हो कार्पोरेट सुधारः गोयल

नईदिल्ली (आरएनएस)। निजी क्षेत्र के येस बैंक संकट के मद्देनजर बैंकों को मजबूत करने की गुरुवार को राज्य सभा में मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विजय गोयल ने शून्य काल में विशेष उल्लेख के जरिए कहा कि हाल ही में येस बैंक के संकट से सभी वाकिफ हैं और इसके मद्देनजर ग्राहकों को हुई दुश्वारियां सबके संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि इससे पहले आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के घोटाले भी सामने आये हैं। इन सब परिस्थितयों के आलोक में बैंकों को दिवालिया होने से बचाने के लिए कार्पोरेट सुधारों की महती आवश्यकता है। गोयल ने भारतीय रिजर्व बैंक के कार्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े नियमों को बदले जाने की मांग करते हुए कहा कि बैंकों की कार्यप्रणाली पर निरंतर नजर रखी जानी चाहिए।

पोलैंड बॉर्डर बंद होने से 50 किमी तक लंबा जाम लगा

वारसा (पोलैंड)। पोलैंड के बॉर्डर पर करीब 50 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए अपने सभी बॉर्डर बंद करने का फैसला लिया है। स्थानीय मीडिया को मुताबिक लोगों को घंटों जाम में इंतजार करना पड़ रहा है। जर्मनी, यूक्रेन और चेक रिपब्लिक के लोग पोलैंड से निकल रहे हैं। पोलैंड सरकार ने विदेशी यात्रियों को लिए अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक 8,500 लोग पोलैंड छोड़कर जा रहे हैं। कई देशों के ये लोग यहां काम कर रहे थे। अब ये महामारी के डर से अपने-अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। कई ट्रक ड्राइवर सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रकों के लिए सरकार को नियमों में ढील देनी चाहिए

» कोरोना वायरस का असर

थी। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को विदेश की यात्रा रोकने का आदेश दिया।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने विदेश यात्रा पर अनिश्चितकाल के प्रतिबंध की घोषणा की। मॉरिसन ने इस महामारी पर कहा, 'यह 100 साल में एक बार होने वाली घटना है। हमने प्रथम विश्व युद्ध के अंत से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की चीज नहीं देखी है।' उधर, दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर के तट पर एक करूज जहाज और मालवाहक जहाज पर कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका में 1,700 से अधिक लोग फंसे हुए हैं।

इस बीच बेल्जियम की प्रधानमंत्री सोफी विल्म्स ने लोगों को कम से कम पांच अप्रैल तक घरों में रहने के लिए कहा है। केवल उन लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें चिकित्सा सेवा की आवश्यकता होगी। तुर्की ने कोरोना वायरस से पहली मौत की पुष्टि की है। वहीं, डेनमार्क ने भी 10 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाने और सुपरमार्केट तथा दवाई की दुकानों के अलावा ज्यादातर दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है।

कलियुग में वायरस से हम लड़ नहीं सकतेः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस पर चिंता जताते हुए बुधवार को कहा कि कलियुग में वायरस से हम लड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक हथियार तो हम बना सकते हैं लेकिन वायरस से नहीं लड़ सकते।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि हर 100 साल में इस तरह की महामारी फैलती है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि इंसान की हैसियत इन वायरस के सामने बौनी पड़ जाती है। आप हथियार तो बना सकते हैं लेकिन इस जानलेवा वायरस से नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने एक सुनवाई के दौरान अदालत में वकीलों की भीड़ को लेकर यह टिप्पणी की।

टीका विकसित करने की जरूरतों पर बैठक

कोविड-19 का टीका विकसित करने के तहत अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) की जरूरतों के मद्देनजर नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने बुधवार को सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के साथ बैठक की।

चीन में दिसंबर में फैले इस वायरस ने दुनियाभर के 155 देशों को चपेट में ले लिया है और करीब दो लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि आठ हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नीति आयोग ने एक ट्वीट में कहा कि उसके सदस्य डॉ वीके पॉल ने सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के साथ कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए आरएंडडी की आवश्यकताओं के मद्देनजर बैठक की अध्यक्षता की।

इसमें कहा गया कि बैठक में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद समेत अन्य विभागों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

रक्षा सचिव ने आरआरआरसी में वेतन लेखा कार्यालय की आधारशिला रखी

नईदिल्ली (आरएनएस)। रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने दिल्ली कैंट के राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट केन्द्र (आरआरआरसी) में वेतन लेखा कार्यालय (अन्य रैंक) - पीएओ (ओआरएस) के भवन निर्माण की आधारशिला रखी।

इस अवसर पर रक्षा सचिव ने रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) और रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) को बधाई दी और उनसे कहा कि वे राष्ट्र की सेवा में अथक परिश्रम करना जारी रखें। उन्होंने आरआरआरसी के कर्मचारियों को भी बधाई दी, जो इस भवन के निर्माण से लाभान्वित होंगे। डॉ. अजय कुमार ने विभाग के लिए 2024 की परिकल्पना कर प्रगतिशील मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सीजीडीए के प्रयासों और उपायों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस भवन का निर्माण हमें नए युग में ले जाएगा और यह डीएडी को और अधिक कुशल बनाएगा, जिससे अपनी भूमिका और अधिक कुशलता से निभाने में इसे मदद मिलेगी। उन्होंने विभाग द्वारा की गई डिजिटल पहलों और काम के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को स्वचालित करने की भी सराहना की।

सीजीडीए श्री संजीव मित्तल ने अपने संबोधन में कहा कि पीएओ ने कार्य के सभी क्षेत्रों में उच्च मानदंड स्थापित किए हैं और इसका उद्देश्य अन्य सेवाओं के साथ लेखा परीक्षा एवं लेखांकन में सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करके इस संगठन को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना है। सीजीडीए ने ई-भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए डीएडी की पहलों की चर्चा की। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया-नकदी प्रबंधन उत्पाद (एसबीआई-सीएमपी) के माध्यम से खाता अधिकारी गैरिसन इंजीनियर्स (एओ जीईएस) में ऑनलाइन भुगतान, पूर्व-सैनिकों की अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) भुगतान के लिए एसबीआई-सीएमपी और डिजिटल इंडिया थीम के अनुरूप रक्षा क्षेत्र के असैन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ते के लिए प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण शामिल हैं। इस अवसर पर चीफ ऑफ स्टाफ, दिल्ली एरिया मेजर जनरल आलोक काकर और अन्य सैन्य एवं असैन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

मप्र के राज्यपाल को है फ्लोर टेस्ट निर्देश देने का अधिकारः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के सियासी संकट पर उच्चतम न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई शुरू हो गई है। स्पीकर की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें देते हुए कहा कि अदालत बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए उन्हें दो सप्ताह जितना पर्याप्त समय दे। जिसपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बागी विधायकों से बात होगी तो क्या उनके इस्तीफे स्वीकार हो जाएंगे तो सिंघवी ने कहा कि यह संभव नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और सरकार बहुमत खो देती है तो राज्यपाल के पास विधानसभा अध्यक्ष को विश्वास मत कराने का निर्देश देने की शक्ति है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बहुमत खो चुकी है या नहीं, यह राज्यपाल तय नहीं कर सकते बल्कि यह सदन तय करता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्यपाल के पास केवल तीन शक्तियां हैं कि सदन कब बुलाना है, कब स्थगित करना है और भंग करना। विधानसभा अध्यक्ष ने वीडियो लिंक से बागी विधायकों से बात करने का न्यायालय का प्रस्ताव ठुकराया।

केंद्र सरकार की 15 प्रदेशों में और हज हाउस बनाने की योजना नहीः नकवी

नई दिल्ली (आरएनएस)। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में बताया कि देश में 15 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में हज हाउस हैं तथा केंद्र सरकार की देश में और हज हाउस बनाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन राज्य इसका निर्माण कर सकते हैं।

उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिये अनेक योजनाएं चला रही है और इसकी सतत निगरानी की जाती है। निचले सदन में छेदी पासवान के प्रश्न के लिखित उत्तर में नकवी ने कहा कि देश में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के तहत 15 हज हाउस हैं जो असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा पश्चित बंगाल में हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि देश में हज हाउस निर्मित करने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है, इसलिये केंद्र सरकार इस प्रयोजनार्थ कोई निधि उपलब्ध नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा कि यद्यपि राज्य सरकारें अपनी राज्य हज समितियों के माध्यम से अपने अपने राज्यों में हज हाउस का निर्माण कर सकती हैं। नकवी ने कहा कि इसके अलावा भारतीय हज समिति इस प्रयोजन के लिये राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हज समितियों को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

लोकसभा में कोरोना वायरस पर बयान दें पीएम मोदी

» विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने और पीएम के बयान की मांग

नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा में गुरुवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने कोरोना वायरस का मुद्दा उठाते हुए इससे निपटने में सरकार के प्रयासों की सराहना की। वहीं दुनिया के कई क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को वापस लाने, जांच की सुविधा का विस्तार करने एवं सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग की।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह एक ऐसा विषय है जिससे केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलकर निपटना है। निचले सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दुनिया में कोरोना वायरस के कारण स्थिति गंभीर है और भारतीय समुदाय के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को इटली, अमेरिका सहित अन्य देशों में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण दुनिया हिल गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सदन को भी संबोधित करें। शिवसेना के विनायक राऊत ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में सरकार ने अच्छा काम किया है। लेकिन सिंगापुर में हवाई अड्डे पर काफी छात्र फंसे हुए हैं और सरकार को उन्हें निकाल कर भारत लाना चाहिए। द्रमुक के दयानिधि मारन ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में सरकार ने काफी सख्त कदम उठाये हैं लेकिन संसद के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है । तृणमूल कांग्रेस के असित कुमाल मल ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से प्रभावित हुई है और इससे निपटने के लिये प्रयास हो रहे हैं। अधिक से अधिक अलग रखने की व्यवस्था सहित अन्य कदम उठाये जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस संबंध में सदन में बयान दें।

शिवसेना के राजन बिचारे ने कहा कि सिंगापुर हवाई अड्डे पर भारत के 58 बच्चें फंसे है जो फिलिपीन में पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे तीन दिन से सिंगापुर हवाई अड्डे पर फंसे हैं। सरकार इन्हें तुरंत निकालने की व्यवस्था करे। कांग्रेस के डीन कुरियाकोस ने कहा कि वह कोरोना वायरस से निपटने में विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों का समर्थन करते हैं।